

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नई ताकत देने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के 40 उपक्रमों (पीएसई) को नई ताकत और दिशा देने जा रही है। उपक्रमों को अधिक कुशल, पारदर्शी और जन-हितैषी बनाने के लिए ठोस रणनीति के तहत काम होगा। प्रदेश में कार्यरत 40 पीएसई में से 97.58 प्रतिशत पूंजी अकेले ऊर्जा क्षेत्र में है। शेष 2.42 प्रतिशत पूंजी में सेवा, निर्माण, उत्पादन, वित्त और व्यापार जैसे क्षेत्रों के सार्वजनिक उद्यम हैं।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम और यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन जैसे प्रमुख उपक्रम राज्य की आर्थिक रीढ़ हैं। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सशक्त करने के लिए चार-सूत्री रणनीति बनाई है। इसके तहत सुशासन को मजबूत करना, अधिकारियों की क्षमता निर्माण,

- 40 उपक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए चार सूत्री रणनीति
- अकेले 97.58 प्रतिशत पूंजी ऊर्जा क्षेत्र में

आधुनिक तकनीक का उपयोग और वित्तीय प्रबंधन को दुरुस्त करना शामिल है। इस रणनीति से बिजली, पानी और अन्य जरूरी सेवाएं पहले से कहीं अधिक सुलभ और किफायती होंगी, जिससे हर परिवार का जीवन आसान होगा। बिजली आपूर्ति में सुधार से गांवों में छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तकनीकी उन्नयन के तहत स्मार्ट मीटर और साइबर सिक्योरिटी पहल से बिजली वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और दक्षता आएगी। पीपीपी माडल और निजी भागीदारी के जरिये औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। सरकार ने प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम तीन साल का कार्यकाल और प्रासंगिक पेशेवर अनुभव सुनिश्चित करने का प्रस्ताव

रखा है। औद्योगिक सुविधा सेल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कदम से सेवाएं बेहतर होंगी।

पीपीपी मोड पर संचालित किए जाएंगे दो और पर्यटक आवास गृह: शिकोहाबाद व इटावा के सुमेर सिंह किला पर्यटक आवास गृहों को अब पीपीपी मोड पर संचालित किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने सोमवार को एमएसएचके बिल्डर्स व मेसर्स अरविंद कुमार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए। एमएसएचके बिल्डर्स शिकोहाबाद स्थित पर्यटक आवास गृह व मेसर्स अरविंद कुमार इटावा के सुमेर सिंह किला पर्यटक आवास गृह का 30 वर्षों तक संचालन करेंगे। पर्यटन निदेशक प्रखर मिश्रा ने एमओयू का आदान-प्रदान किया। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि दोनों पर्यटक आवास गृहों के संचालन से पर्यटकों को काफी सुविधाएं मिलेंगी। इससे पहले घाटे में चल रहे दस से ज्यादा पर्यटक आवास गृहों को पीपीपी मोड पर संचालित करने के लिए एमओयू किया जा चुका है।